Title: Need to look into the demands of Journalists with regard to their wages.

श्री विजय गोयल (चांदनी चौक): मान्यवर, आठ मई को समाचार पत्रों में काम करने वाले प्रायः सभी पत्रकार एवं गैर-पत्रकार कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में राट्रव्यापी हडताल की थी। स्वतंत्र समाचार पत्र हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ माने जाते हैं इसलिए इस चौथे स्तम्भ में होने वाली घटनाओं से हम सभी का चिंतित होना स्वाभाविक है। कर्मचारियों की मांग है कि मणिसाना वेतन आयोग शीघ्र अपनी रिपोर्ट दे ताकि पत्रकारों - गैर पत्रकारों के वेतनमान संशोधित किए जा सकें। समाचारों के मुताबिक प्रबंधकों के संगठन आई0एन0एस0 ने इस आयोग की रिपोर्ट आने से पहले ही न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। स्वाभाविक रूप से इससे आयोग की रिपोर्ट आने में विलम्ब होगा। प्रबंधन और कर्मचारी संगठनों में बने इस टकराव को टालने के लिए प्रधानमंत्री जी ने पहल की है। इस पहल से समाधान निकलने की आशा है, लेकिन कुछ ऐसी मांगे हैं, जिन्हें पूरा करवाने के लिए सरकार को अपने प्रभाव का प्रयोग करना चाहिए। एक, वेतन संबंधी सभी विवाद मणिसाना आयोग के दायरे में विचारार्थ होने चाहिए, दूसरे, आयोग की सिफारिशें लागू करने में सिर्फ एक-तिहाई समाचार पत्रों ने पहल की। यह सिफारिशें लागू न करने पर दौ सौ रूपए जुर्माने का प्रावधान है। इसे एक लाख रूपए तक किए जाने की जरूरत है साथ ही समाचार पत्रों में पत्रकारों को कांस्ट्रेक्ट बेसिस पर रखने की प्रवृति पर भी विचार करने की आवश्यकता है। यह भी सत्य है कि समाचार पत्र निजी स्वामित्व वाले क्षेत्र के हैं, परन्तु जिस प्रकार सरकार कई तरह की रियायतें देकर उन्हें उनके संचालन में सहयोग करती है, वैसे ही सहयोग से इनमें काम करने वाले पत्रकारों और गैर पत्रकार कर्मचारियों को भी राहत पहुंचाने के प्रबंध किए जाएं, स्वतंत्र और स्वस्थ लोकतंत्र के लिए यह जरूरी है।